भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3570

दिनांक 13 मार्च, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

तमिलनाडु में पीएम-एबीएचआईएम के अंतर्गत प्राप्त प्रगति

†3570. श्री सी. एन. अन्नादुरईः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने तमिलनाडु में विशेष रूप से ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य केंद्रों, नैदानिक प्रयोगशालाओं और क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स को सुदृढ़ करने के संबंध में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्य में सभी स्वास्थ्य सुविधाओं के व्यापक आकलन से अवसंरचना और क्षमता अंतराल की व्यवस्थित पहचान और प्राथमिकता तय करने में मदद मिली है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास उक्त मूल्यांकनों के बाद स्वास्थ्य सेवा की तैयारी, सेवा वितरण और अवसंरचना के लचीलेपन में हुए सुधारों पर कोई आंकड़ा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पीएम-एबीएचआईएम के तमिलनाडु के कार्यान्वयन से उभरने वाले सर्वोत्तम अभ्यासों को प्रलेखित किया गया है और देश के अन्य राज्यों के साथ साझा किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का पीएम-एबीएचआईएम के अंतर्गत सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए समय पर वित्तपोषण, तकनीकी सहायता और निगरानी के माध्यम से तमिलनाडु को और सहायता प्रदान करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रताप राव जाधव)

(क) से (ङ): भारत सरकार नियमित रूप से प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) के अंतर्गत प्राप्त प्रगति की समीक्षा आवधिक समीक्षा बैठकों, निगरानी पोर्टलों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से करती है। तमिलनाडु में, मिशन के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को सुदृढ़ करने, एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं की स्थापना और जिला

अस्पतालों में गहन चिकित्सा कक्षों की स्थापना के संबंध में प्रगति की निगरानी की जा रही है। राज्य ने पीएम-अभिम के अंतर्गत स्वीकृत प्रस्तावों और समय-सीमाओं के अनुसार इन स्वास्थ्य अवसंरचना घटकों के संचालन और उन्नयन में प्रगति की सूचना दी है, और मिशन के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय द्वारा इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) और पीएम-अभिम के तहत निगरानी एक सुदृढ़, बहुस्तरीय ढांचे के माध्यम से की जाती है, जिसमें तमिलनाडु सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ एनपीसीसी बैठकों के दौरान अनुमोदित लक्ष्यों के सापेक्ष राज्यवार प्रमुख उपलब्धियों की समीक्षा, आउटपुट-आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क (ओओएमएफ) के माध्यम से प्रदर्शन का नियमित मूल्यांकन शामिल है। इसके अतिरिक्त, वार्षिक कॉमन रिव्यू मिशन (सीआरएम) कार्यक्रम कार्यान्वयन, स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण और प्रमुख संकेतकों पर प्रगति का स्वतंत्र, जमीनी आकलन प्रदान करते हैं, जिससे कमियों की पहचान, सुधार और राज्य एवं जिला स्तर पर जवाबदेही को तय करने में मदद मिलती है।

तमिलनाडु सहित सभी राज्यों में पीएम-अभिम योजना के कार्यान्वयन से सामने आने वाली सर्वोत्तम प्रथाओं का दस्तावेजीकरण किया जा रहा है और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय समीक्षा बैठकों, कार्यशालाओं और तकनीकी परामर्शों के माध्यम से इनसे प्राप्त जानकारी का प्रसार किया जा रहा है। ये मंच राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के बीच जानकारी के आदान-प्रदान को सुगम बनाते हैं, जहां आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, निदान प्रयोगशालाओं और गहन चिकित्सा अवसंरचना को मजबूत करने से संबंधित नवाचारों और प्रभावी कार्यान्वयन रणनीतियों को व्यापक रूप से अपनाने के लिए साझा किया जाता है। इस संबंध में, पीएम-अभिम योजना के तहत जन स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत करने पर राष्ट्रीय कार्यशालाओं का आयोजन अगस्त 2025 में किया गया था ताकि सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान को बढ़ावा दिया जा सके और राज्यों में कार्यान्वयन में तेजी लाई जा सके।

पीएम-अभिम एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें कुछ केंद्रीय क्षेत्र के घटक शामिल हैं, जिसका वित्त वर्ष 2021 -22 से वित्त वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए कुल परिव्यय 64,180 करोड़ रुपये है। पीएम-अभिम के सीएससी घटक के तहत, तमिलनाडु को वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए 708 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, जिला स्तर पर 38 एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं और जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में 37 क्रिटिकल केयर ब्लॉकों के लिए 1656.32 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

इसके अलावा, पंद्रहवें वित्त आयोग के स्वास्थ्य अनुदान के तहत, तमिलनाडु को वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए 4249.42 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें से अब तक 4249.28 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। इन निधियों से 842 भवनविहीन उप-स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी), 258 भवनविहीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), 105 भवनविहीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी), 386 ब्लॉक जन स्वास्थ्य इकाइयों और 1207 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण में सहायता मिलती है।

व्यय विभाग (डीओई) द्वारा दिनांक 13.07.2023 को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, वित्त मंत्रालय ने नई निधि प्रवाह व्यवस्था यानी एसएनए स्पर्श शुरू की है, जिसके तहत सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए समय पर निधि जारी की जाती है। वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2024-25 तक तमिलनाडु राज्य के लिए पीएम-अभिम के तहत केंद्र द्वारा जारी की गई धनराशि का विवरण इस प्रकार है:

(रुपये करोड़ में)

क्र. सं.	**राज्य**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
1	तमिलनाडु	150.42	279.36	224.99

नोट: उपरोक्त धनराशियां केंद्र सरकार द्वारा दिए गए अनुदानों से संबंधित हैं और इनमें राज्य सरकार का हिस्सा शामिल नहीं है।

*****